सं. ए-45011/3/2022-प्रशासन III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को अगस्त, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

10/10/2022

(रविन्द्र कुमार)

निदेशक (प्रशा. IV और समन्वय)

दूरभाष नं. 2309-5244

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्यमंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (ईए) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, (दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. श्री वी.अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (वित्त) ।
14. श्रीमति मनीषा सिन्हा, अपर सचिव (प्रशा./ सीएंडसी/ ओएमआई) ।
15. आर्थिक कार्य विभाग में सभी प्रभागों के प्रमुख।
    संयुक्त सचिव (आईपीपी/संयुक्त सचिव (आईएसडी)/संयुक्त सचिव (आईएनवी)/ संयुक्त सचिव (बजट)/सभी सलाहकार/सीएएए
16. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
17. गार्ड फाइल – 2022

संख्या.क-45011/3/2022-प्र.शा.III

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

विषयः अगस्त, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश

I. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:

वृहद आर्थिक सिंहावलोकनः

कोविड-19 से उबरने और रूस-यूक्रेन संघर्ष के नकारात्मक फैलाव पर, 2022-23 की पहली तिमाही में एक मजबूत आर्थिक विकास ने भारत को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यूके से आगे निकलने में मदद की है। 2022-23 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी अब 2019-20 के अपने क्रमिक स्तर से लगभग 4% आगे है, इस प्रकार महामारी के बाद के चरण में भारत के विकास पुनरुद्धार के लिए एक मजबूत शुरुआत है।

संपर्क-गहन सेवा क्षेत्र में 2022-23 भवन में रुकी हुई मांग और टीकाकरण के लगभग सार्वभौमिकरण के विकास को गति देने की संभावना है। उपभोक्ताओं की बढ़ती भावनाओं और बढ़ते रोजगार के कारण निजी खपत में तेजी से उछाल आने वाले महीनों में विकास को बनाए रखेगा।

चालू वर्ष में निजी खपत में वृद्धि और उच्च क्षमता उपयोग ने 2022-23 की पहली तिमाही में निवेश दर को पिछले दशक में अपने उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए पूंजीगत व्यय चक्र को और मजबूत किया है। निजी निवेश में अधिक परियाजनाओं की भी सरकार के बढ़ते हुए पूंजीगत व्यय द्वारा भी सहायता की गई है जो अगस्त 2022-23 तक पिछले वर्ष के क्रमिक स्तर की तुलना में 35% अधिक रहा है। पूंजीगत व्यय पर सरकार का खर्च जारी रहने की संभावना है क्योंकि चालू वर्ष की शेष अवधि में राजस्व वृद्धि में उछाल कम रहने की उम्मीद है।

2022-23 की पहली तिमाही के दौरान आर्थिक गतिविधियों में व्यापक-आधारित वृद्धि रोजगार संकेतकों में सुधारों में परिलक्षित होती है। ईपीएफओ में निवल (पेरोल) वेतन वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2022-23 की पहली तिमाही में दोगुना हो गई। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) दिखाता है कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर लगातार चौथी तिमाही में घट कर 2022-23 की पहली तिमाही में 7.6% हो गई है, जो कि पूर्व-महामारी स्तर से कम है। मनरेगा के तहत काम की मांग मई से कम हो रही है और पिछले दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में अगस्त 2022 में सबसे कम थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में संभावित कमी का संकेत है।

जुलाई और अगस्त 2022 के दौरान उच्च आवृत्ति संकेतकों (एचएफआई) के मजबूत प्रदर्शन के साथ-साथ 2022-23 की दूसरी तिमाही में पहली तिमाही की विकास गति निरंतर बनी हुई है। अगस्त 2022 में भारत के लिए समग्र पीएमआई बढ़कर 58.2 हो गया, जो विस्तार की तेज गति का संकेत है। हालांकि, इसके विपरीत, वैश्विक समग्र पीएमआई, मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के साथ अगस्त 2022 में संकुचन चरण में 49.3 तक गिर गया है।

भारत के आर्थिक विकास पर अपेक्षाकृत स्पष्ट दृष्टिकोण और इसके रोजगार के स्तर में सुधार बाहरी क्षेत्र में देश की अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में भी परिलक्षित होता है। उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, निरंतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और मजबूत निर्यात आय ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण और भू-राजनीतिक संघर्ष से उत्पन्न चालू खाता घाटे के बढ़ने के खिलाफ एक उचित बफर प्रदान किया है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) दोनों में मुद्रास्फीति एक सामान्य घटना रही है। हालांकि, दोनों के लिए ट्रिगर कुछ अलग रहे हैं, जो यह भी बताता है कि क्यों एई में मुद्रास्फीति का दबाव है और रूस-यूक्रेन संघर्ष की तारीख से पहले के रहे हैं। कोविड-19 के प्रकोप के जवाब में एई द्वारा अपनाए गए असाधारण उपायों में इन देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नकदी (लिक्विडिटी) का एक महत्वपूर्ण अन्तः क्षेपण शामिल था, जिसने उनके बड़े वित्तीय पैकेज को वित्तपोषित किया। अब, जैसा कि एई के मौद्रिक प्राधिकरण मुद्रास्फीति को सीमित करने और चलनिधि की अधिकता से जूझने के लिए दौड़ते हैं, उन्हें एक अंशांकित तरीके से अतिरिक्त लिक्विडिटी को अवशोषित करने का एक अविश्वसनीय कार्य का सामना करना पड़ता है। भारत अचानक विकास को रोके बिना अपने लिक्विडिटी स्तरों को जांचने की बेहतर स्थिति में है।

जबकि लगातार उच्च चलनिधि एई में मुद्रास्फीति की अनम्यता को आंशिक रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, भारत में मुद्रास्फीति, एक निवल वस्तु-आयात करने वाला देश, बाहरी रूप से स्थित बहिर्जात दबावों का गौण परिणाम रहा है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि घरेलू कीमतों में वृद्धि में परिलक्षित हुई, हालांकि सरकार द्वारा समय पर किए गए हस्तक्षेपों के कारण घरेलू कीमतों में वृद्धि अपेक्षाकृत मामूली थी। इसके अलावा, जैसे-जैसे ये बाहरी दबाव कम होते हैं, भारत में मुद्रास्फीति के दबाव भी कम होने की संभावना है। कई संकेतक पहले से ही बाहरी दबावों में नरमी की ओर इशारा कर रहे हैं। मार्च 2022 में अपने चरम पर पहुंचने के बाद औद्योगिक धातुओं और खाद्य तेल की कीमतों में नरमी आई है, जिसके कारण एई में मंदी की आशंका है। जून 2022 के महीने में शिखर (पीक) के बाद से अगस्त तक कच्चे तेल की कीमतों में 19.1% की गिरावट आई है। बंदरगाह में संकुलन में गिरावट के साथ आपूर्ति श्रृंखला बहाल हो रही है। प्रभाव अप्रैल 2022 से सीपीआई-सी और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में गिरावट में पहले से ही परिलक्षित होता है। सीपीआई-सी मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में 7.8% की तुलना में

अगस्त 2022 में 7% थी। इसी तरह, डब्ल्यूपी आई मुद्रास्फीति अप्रैल में 15.4% से घटकर अगस्त में 12.4% हो गई है। कुल मिलाकर, भारत में मुद्रास्फीति का दबाव सरकार द्वारा प्रशासनिक उपायों की पूर्व क्रमिक व्यवस्था, चुस्त मौद्रिक नीति और अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं (कमोडिटी) की कीमतों में ढील और आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाओं के साथ गिरावट पर प्रतीत होता है।

ऐसे समय में जब धीमी वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति दुनिया की अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है, भारत की वृद्धि सुदृढ़ रही है और मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। टीकाकरण और अच्छी तरह से अंशांकित अल्पकालिक नीतिगत उपायों के तेजी से कवरेज ने अशांत समय के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कुशलता से नकारात्मक किया है, जो आने वाले वर्षों में एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहा है।

विकास के लिए नकारात्मक जोखिम तब तक बना रहेगा जब तक भारत शेष विश्व के साथ एकीकृत हो जाता है। न ही मुद्रास्फीति के मोर्चे पर आत्मतुष्टि (कम्पैसन्सी) की कोई जगह है क्योंकि खरीफ सीजन के लिए कम फसलों की बुवाई के लिए बिना कृषि निर्यात को खतरे में डाले कृषि वस्तुओं के स्टॉक और बाजार की कीमतों के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जैसे-जैसे फेड की बैलेंस शीट सिकुड़ने लगती है, यह पूंजी बाजारों में जोखिम से बचने के एक नए चरण की शुरुआत कर सकता है, जिससे वैश्विक पूंजी प्रवाह बाधित हो सकता है। इसके अलावा, भारत का आयात तेजी से बढ़ रहा है और इसलिए, उन्हें सुविधापूर्ण रूप से वित्तपोषित करने को उच्च प्राथमिकता देनी होगी। शीत माह में, उन्नत राष्ट्रों में ऊर्जा सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करने से भू-राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है, जो भारत की अब तक की ऊर्जा जरूरतों को दक्षतापूर्ण संभालने का परीक्षण कर सकता है।

भारत के लिए अपनी विकास आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सतर्क और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और विश्वसनीय मौद्रिक नीति आवश्यक रहेगी। सार्वजनिक नीति के ये दोनों स्तंभ सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए बेंचमार्क उधारी लागत को कम करने में सक्षम होंगे, जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण में सुविधा होगी। सरकार के सभी स्तरों पर आस्ति मुद्रीकरण के मजबूत लक्ष्य से ऋण पूंजी और इसलिए ऋण सेवा लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इससे जोखिम प्रीमियम में गिरावट आएगी और भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार होगा।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

(i) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सभी कपास वायदा अनुबंधों को 29 अगस्त 2022 से अनुबंध विनिर्देशों को फिर से देखने और संशोधित करने के लिए एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था।

(ii) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास संस्थानो के साथ निम्नलिखित ऋण/अनुदान समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

(क) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से 96.3 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण।

(ख) दूसरे तमिलनाडु आवासन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक से 190 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण-डीपीएल

(ग) 'तमिलनाडु में नगर अवसंरचना विकास परियोजना' के लिए केएफडब्ल्यू-जर्मन विकास बैंक से 20 मिलियन यूरो का अनुदान

इसके अलावा, विश्व बैंक के साथ 350 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर स्वास्थ्य क्षेत्र परियोजना, सिस्टम्स रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात (एसआरईएसटीएचए-जी) के साथ वार्ता।

(iii) इस महीने के दौरान निम्नलिखित स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा (लाइन ऑफ क्रेडिट) को मंजूरी दी गई।

(क) वित्तीय विकास परियोजनाओं के लिए मालदीव सरकार को 100 मिलियन अमरीकी डालर।

(ख) रक्षा संबंधी परियोजनाओं और अन्य उद्देश्यों के लिए आर्मेनिया सरकार को 100 मिलियन अमरीकी डालर।

(iv) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं या उनमें भाग लिया गया.

(क) बहुपक्षीय विकास बैंकों/द्विपक्षीय संस्थानों से वित्तपोषण की मांग करने वाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जांच समिति की 131वीं बैठक

(ख) प्रक्रियाधीन (पाइपलाइन) परियोजनाओं की तैयारी की समीक्षा के लिए विश्व बैंक के साथ बैठक

(ग) जलवायु संबंधी जोखिमों के लिए पर्यवेक्षी और नियामक दृष्टिकोण पर अंतिम रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा करने के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के जलवायु जोखिम पर कार्य समूह (डब्ल्यूजीसीआर) की बैठक

(घ) द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर भारत और सऊदी अरब के बीच चौथे दौर की चर्चा

(ङ) भारत और उरुग्वे के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर प्रारंभिक चर्चा

(च) द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी)/निवेश अध्याय पर भारत और यूके के बीच वार्ता का छठा दौर

(छ) द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते (बीआईपीए) पर कनाडा के साथ चर्चा

(ज) पीपीपी मोड के तहत यूपी के छह जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए यूपी सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 42वीं अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की बैठक

(झ) निवेश संचालन और निवेश संचालन पर विचार करने के लिए तिमाही निगरानी रिपोर्ट/पाइपलाइन अद्यतन (अपडेट) पर विचार करने के लिए एशिया अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के निदेशक मंडल की बैठक

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी के निर्देशों/आदेशों का पालन न करना

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में श्री अनंत नारायण गोपालकृष्णन की एसीसी नियुक्ति को प्रभावित करने वाली अधिसूचना जारी है।

5. माह के दौरान स्वीकृत एफडीआई प्रस्तावों का विवरण और विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	:	शून्य
विभाग में स्वीकृति की प्रतीक्षा	:	07